www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी खबर

वर्ष – 05 | अंक – 100 | जौनपुर, शुक्रवार, 27 नवम्बर 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

तमिलनाडु सरकार ने नहीं माना था सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि तिरुपरंकुद्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून स्तंभ पर परंपरागत धार्मिक दीप नहीं जलाए जाने से जुड़े विवाद के संबंध में दायर अवमानना याचिकाओं और अन्य आवेदनों को 27 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ को मामले में पेश वकीलों ने बताया कि इस मुद्दे पर कई अवमानना याचिकाएं और आवेदन दायर किए गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने विवादित दीपथून स्तंभ पर धार्मिक दीप नहीं जलाए जाने को लेकर बुधवार को शीर्ष अदालत से माफी मांगी थी और इसके लिए भगवान मुरुगन (सुब्रमण्यस्वामी) मंदिर के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया था। शीर्ष अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना कार्यवाही शुरू करने से इनकार कर दिया था, लेकिन कहा था कि यदि इस संबंध में कोई याचिका दायर की जाती है, तो वह उस पर सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद सोमवार को तिरुपरंकुंद्रम में वार्षिक कार्तिगई दीपम केवल उसके पारंपरिक स्थल उच्ची पिल्लैयार मंडपम में जलाया गया, न कि पहाड़ी पर स्थित पत्थर के स्तंभ यानी दीपथून। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अधिकारियों पर शीर्ष अदालत के निर्देशों का जानबूझकर पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए अनुरोध किया ।

रणबीर कपूर की रामायण के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई

नई दिल्ली, (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रणबीर कपूर की फिल्म रामायण राइज ऑफ ए लेजेंड की रिलीज को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन्हें फिल्म में दिखाए गए महाकाव्य के नजरिए से असहमति है, वे अपना अलग नजरिया पेश करने के लिए खुद की फिल्म बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत पर सवाल उठाए। बेंच ने कहा कि फिल्म पहले ही सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और जो लोग इसे देखना चाहते थे, वे देख चुके हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने बेंच को बताया कि यह याचिका 23 नवंबर को दर्ज की गई थी, लेकिन अभी तक इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है। जिन्हें इसे देखना था, वे देख चुके हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म निर्माताओं ने रामायण के चित्रण में कई पौराणिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की है। सुनवाई के दौरान जब वकील ने दलील दी कि फिल्म में कई तथ्यों को तोड़–मरोड़कर पेश किया गया है, तो जस्टिस बागची ने जवाब दिया कि उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से फिल्म बनाई है।

सैफई सिंडिकेट नहीं गिन पाएगा नियुक्ति पत्र बांटने की गति - सीएम योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से चयनित 1594 लेखा परीक्षकों और सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जिस तेजी से नियुक्ति पत्र बांट रही है सैफई सिंडिकेट उसकी गति नहीं गिन पाएगा, क्योंकि उसे सिर्फ नोट गिनना आता है।वर्ष 2017 से पहले फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह प्रदेश में नियुक्तियां होती थी। आवेदन कोई करता था और नियुक्ति पत्र किसी और को दिया जाता था। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी



प्रतिष्ठान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में 201 लेखा परीक्षक और 1393 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र दिया। उन्होंने कहा कि अब तक 9.70 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। यह संख्या सपा के चार और बसपा के तीन कार्यकाल की कुल भर्तियों से दोगुने से भी अधिक है। अगले सप्ताह 50 हजार और नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इनमें आठ हजार लेखपाल, 42 हजार होमगार्ड और शिक्षा आयोग के दो हजार चयनित अभ्यर्थी नौकरी पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं मुन्ना भाई गैंग के सरगरना के बयान को पढ़ रहा था। उनके समय में चयन की प्रक्रिया मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म की तरह थी। परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र कोई मुन्ना भाई लेकर चला जाता था। वर्ष 2015–16 में हाईस्कूल, इंटर और स्नातक में थर्ड डिवीजन पाने वाले अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा का टॉपर बना दिया गया। सीएम ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले मेहनत की कोई कीमत नहीं थी। एक भी भर्ती ईमानदारी से नहीं हुई। उन्होंने कहा मेरिट का अपमान महापाप है। पिछली सरकारों ने यह पाप किया था। इन पापों की सजा जनता ने दी है और आगे भी देगी। नियुक्ति पत्र युवाओं के परिश्रम का सम्मान है। उन्होंने कहा मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से कहूंगा कि आपने बताया नहीं कि 25 लाख नियुक्ति पत्र कहां देंगे। लोगों को अपने अतीत के बारे में बताइए।

`ज्ञानवान की सत्संगति में सार्थक चर्चाओं से परिष्कृत होती है विवेक और बौद्धिक चेतना – पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को एक संस्कृत सुभाषित शेयर किया, जिसमें सज्जन, विद्वान और ज्ञानवान व्यक्तियों की संगति जैसे प्रमुख गुणों के बारे में बताया गया है। पीएम मोदी ने सुभाषित के जरिए संदेश दिया कि सार्थक चर्चाएं और विचारों का आदान–प्रदान मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित करते हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर संस्कृत सुभाषित शेयर करते हुए लिखा इस संस्कृत सुभाषित का अर्थ है, "सज्जन, विद्वान और ज्ञानवान व्यक्तियों की सत्संगति में होने वाली सार्थक चर्चाएं व विचारों का आदान–प्रदान मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित करते हैं। ऐसी ज्ञानपरक चर्चाएं न सिर्फ श्रवण के लिए आनंददायक होती हैं, अपितु व्यक्ति की विचारशक्ति, विवेक और बौद्धिक चेतना को भी परिष्कृत करती हैं और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जाग्रत करती हैं।" यह प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद्भागवत महापुराण के तृतीय (तीसरे) स्कंध के 25वें अध्याय का 25वां श्लोक है। भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को भक्ति योग और सत्संग की महिमा समझाते हुए कहा था। जब माता देवहूति ने अपने पुत्र भगवान कपिल से संसार के बंधनों से मुक्त होने और भक्ति प्राप्त करने का उपाय पूछा, तब भगवान कपिल ने सत्संग को सबसे सरल और प्रभावी मार्ग बताया। इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने समझाया कि संतों की संगति में ही ईश्वर की कथाओं में रुचि जागती है, जो जीव को क्रमशः मोक्ष तक ले जाती है।



बजट 2027 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की चर्चा, रोजगार और आर्थिक विकास पर मिले सुझाव

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट–पूर्व परामर्श में 13 क्षेत्रों और विभिन्न हितधारक समूहों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इन चर्चाओं में नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, सामाजिक एवं आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था को अधिक सक्षम तथा भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार बनाने पर जोर दिया गया। इस परामर्श में उद्योग संघों, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, भारतीय उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, युवाओं और अन्य पेशेवरों ने भाग लिया। इसमें कृषि एवं ग्रामीण विकास, विनिर्माण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (डैडम्) और स्टार्टअप, पूंजी बाजार, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा (ठथ्ै), सूचना प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा एवं सतत विकास, रोजगार एवं श्रम, आवास, शहरीकरण एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं सामाजिक मुद्दे, अनुसंधान एवं विकास तथा उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल रहे।



इसके अलावा स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं खेल, युवा मामले और अर्थशास्त्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। आधिकारिक बयान के मुताबिक, आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों के सचिव भी इन चर्चाओं में शामिल हुए। हितधारकों ने ऐसे सुधारों की जरूरत पर जोर दिया, जो व्यापक और समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए ।

प्रामाणिक एवं प्रभावी आयुर्वेद के माध्यम से समाज की सेवा करें आयुर्वेद महाविद्यालय – राष्ट्रपति मुर्मु

केरलम, (एजेंसी)। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 27 नवंबर, 2026 को केरलम के त्रिशूर में वैद्यरत्नम् आयुर्वेद कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोहों के समापन समारोह में शामिल हुईं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आयुर्वेद महाविद्यालयों को प्रामाणिक एवं प्रभावी आयुर्वेद के माध्यम से समाज की सेवा करनी चाहिए। साथ ही, उन्हें समसामयिक और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप आयुर्वेद की शिक्षा प्रदान करते हुए वर्तमान और भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सक्षम विशेषज्ञ तैयार करने चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि केरलम का योगदान केवल आयुर्वेद की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य ने आयुर्वेद की शास्त्रीय शिक्षा की समृद्ध



और जीवंत परंपरा को संरक्षित करने तथा आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केरलम ने वैद्य परिवारों की पीढ़ियों से चली आ रही चिकित्सा संबंधी ज्ञान–परंपरा को समृद्ध किया है। प्रामाणिक आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण की परंपराएं भी राज्य में आज निरंतर फल–फूल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि आयुर्वेद की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसका प्रामाणिक साहित्य केवल संस्कृत भाषा तक सीमित नहीं रहा है। केरलम में मलयालम और मणिप्रवालम भाषाओं में भी अनेक मौलिक ग्रंथों की रचना की गई है और टीकाएं लिखी गई हैं। यह आयुर्वेद की ज्ञान परंपरा की व्यापकता और भाषाई समृद्धि को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रत्येक आयुर्वेद महाविद्यालय को प्रामाणिक एवं प्रभावी आयुर्वेद के माध्यम से समाज की सेवा करनी चाहिए। इन संस्थानों में समसामयिक और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि ऐसे विशेषज्ञ तैयार हो सकें, जिनमें वर्तमान और भावी पीढ़ियों की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की समझ और दूरदृष्टि हो। उन्होंने यह जानकर प्रसन्नता व्यक्त की कि वैद्यरत्नम् आयुर्वेद कॉलेज की कार्य–संस्कृति इसी आदर्श के अनुरूप है। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि वैद्यरत्नम् आयुर्वेद कॉलेज जैसे संस्थान वर्ष 2047 तक स्वस्थ और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अपना योगदान दे रहे हैं।

वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की विकास गाथा मजबूत, ऋण बाजारों को व्यापक बनाने पर पीयूष गोयल का जोर

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की विकास गाथा मजबूत, लचीली और भरोसेमंद बनी हुई है। भारत ऋण पूंजी बाजार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के आर्थिक प्रदर्शन, पिछले 12 वर्षों में हुए सुधारों, बढ़ते व्यापारिक अवसरों और भारत की विकास संबंधी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में ऋण बाजारों की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देने, व्यापक ऋण व्यवस्था विकसित करने और अर्थव्यवस्था की वित्तपोषण जरूरतों को पूरा करने के लिए नवोन्मेषी वित्तीय साधनों की आवश्यकता पर भी जोर दिया।



पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8: आर्थिक वृद्धि दर्ज की है और विश्वास जताया कि दूसरी तिमाही में भी विकास की गति कायम रहेगी। सकल स्थिर पूंजी निर्माण में करीब 12: की वृद्धि हुई है, जबकि चालू वर्ष के पहले सात महीनों में भारत का निर्यात 570 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि देश एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को मई में निर्धारित किए जाने के समय काफी महत्वाकांक्षी माना गया था। उन्होंने करीब 19: ऋण वृद्धि को भी ऋण बाजारों के लिए सकारात्मक संकेत बताया। गोयल ने कहा कि भारत ने दो जारी युद्धों, तेल कीमतों में उतार–चढ़ाव, शुल्क संबंधी अनिश्चितताओं, वैश्विक व्यापारिक अवसरों में बदलाव, समुद्री मार्गों में व्यवधान और हवाई यात्रा को प्रभावित करने वाले छिटपुट हमलों जैसी चुनौतियों के बीच अपनी आर्थिक मजबूती साबित की है। इन परिस्थितियों के बावजूद भारत की विकास गाथा पर वैश्विक विश्वास कायम रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने सुधारों की प्रक्रिया जारी रखी, नई नीतियां लागू कीं, कारोबार सुगमता में सुधार किया और व्यवसायों तथा विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद के लिए अपनी नीतियों को खुला एवं अनुकूल बनाए रखा।

सरकार का होगा बहुत महत्वपूर्ण कामकाज, सार्थक चर्चा होनी चाहिए – किरेन रिजिजू

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने 4 दिन का संसद सत्र बुलाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखा है। रिजिजू ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "सरकार ने संसद का चार दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को पत्र भेजा गया है। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को लोकसभा में महत्वपूर्ण सरकारी कार्यकाज रखा जाएगा। इसके बाद वही कार्य 2 और 3 दिसंबर को राज्यसभा में लिए जाएंगे।" उन्होंने कहा, "मैंने सभी राजनीतिक दलों से भी अपील की है, और मैंने प्रमुख दलों के नेताओं से बात की है। कुछ सांसदों ने सोशल मीडिया और अन्य मीडिया आउटलेट्स पर बयान जारी कर कहा है कि सरकार नियमों के अनुसार काम नहीं कर रही है। ऐसे हल्के बयान नहीं दिए जाने चाहिए, क्योंकि जब भी कोई महत्वपूर्ण बिल या बिजनेस लाया जाना होता है, सरकार सत्र बुला सकती है। यह स्थापित परंपरा रही है। रिजिजू ने कहा, "मैं अतीत में नहीं जाना चाहता, लेकिन पहले भी ऐसे उदाहरण रहे हैं जब पिछले सत्र को स्थगित किए बिना एक के बाद एक सत्र बुलाया गया। यह लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है। जब भी कोई महत्वपूर्ण बिल या देश के लिए कोई काम करना होता है, सरकार संसद का सत्र बुलाती है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। जब सरकार विशेष सत्र बुलाती है, तो इसका मतलब है कि कुछ विशेष काम किया जाना है। महत्वपूर्ण बिल और देश से जुड़े मामले उठाए जाते हैं, इसीलिए ऐसा सत्र बुलाया जाता है।" उन्होंने कहा, "मैं सभी दलों के नेताओं और सांसदों से अनुरोध करूंगा कि पूरे दिल से जो भी बिल लाए जाएंगे।



डाकघर के इन्फ्रास्ट्रक्चर में आएगा बड़ा बदलाव, लॉजिस्टिक्स क्षमता होगी बेहतर – ज्योतिरादित्य सिंधिया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को कहा कि कैबिनेट की ओर से डाक परिचालन योजना और संपदा प्रबंधन योजना को करीब 2,500 करोड़ रुपए की मंजूरी मिलने से डाकघर के इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आएगा। केंद्रीय मंत्री में सिंधिया ने कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में विभाग की अगली पांच–वर्षीय योजना के तहत 'डाक परिचालन योजना' के लिए लगभग 1,140 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। इसके अलावा, 'एस्टेट मैनेजमेंट स्कीम' के लिए 1,400 रुपए करोड़ मंजूर किए गए। इस तरह, दोनों योजनाओं के लिए करीब 2,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इससे डाकघरों के इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आएगा। इसमें डाकघरों के कार्यालय, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, मार्केटिंग सिस्टम, फर्स्ट माइल, मिडिल माइल और लास्ट–माइल लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी शामिल है। केंद्र सरकार ने बुधवार को 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल (वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31) के दौरान डाक संचालन योजना और संपदा प्रबंधन योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इस योजना के लिए क्रमशरू 1,141 करोड़ रुपए और 1,491 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट निर्धारित किया गया है। डाक संचालन योजना का उद्देश्य देशभर में डाक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, परिचालन दक्षता में सुधार करना और लॉजिस्टिक्स, ई–कॉमर्स एवं डिजिटल सेवाओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करना है। कैबिनेट द्वारा जारी बयान में कहा गया,।

पांच वर्ष में दुनिया में सबसे तेज गति से हुआ अयोध्या का विकास महापौर

तकनीकी विकास को ध्यान में रखकर तैयार करें नवनिर्माण की परियोजनाएं – नगर आयुक्त

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि बीते पांच वर्षों में अयोध्या का विकास दुनिया के इतिहास में सबसे तेज गति से हुआ है।यहां के प्रशासन,विकास प्राधिकरण, नगर निगम ने कुशल अभियंताओं के साथ मिलकर कनेक्टिविटी, स्वच्छता से लेकर नव निर्माण तक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।नई तकनीक के इस्तेमाल से अयोध्या न केवल सतत विकास की ओर अग्रसर है, बल्कि स्मार्ट सिटी के रूप में भी विकसित हो रही है।महापौर गुरुवार को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में रायबरेली बाईपास स्थित कल्याण मंडपम में आयोजित 'जन आवास के लिए नई निर्माण प्रौद्योगिकियां'विषयक कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार और अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराग जैन के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया।महापौर ने कहा कि अयोध्या में निर्माण कार्यों से निकलने वाली वेस्टेज सामग्री से टाइल्स बनाने का प्रस्ताव भी लंबित है।इस दिशा में पहल होने से निर्माण अपशिष्ट के बेहतर उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने कहा कि अभियंताओं को नवीन तकनीकों से निरंतर रूबरू होना चाहिए। निर्माण अथवा विकास की कोई भी परियोजना तैयार करते समय नई तकनीकों को विशेष रूप से शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने सड़क निर्माण में आधुनिक तकनीक के समावेश पर जोर देते हुए कहा कि भवन निर्माण के दौरान प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का भी ध्यान रखना जरूरी है।अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराग जैन ने कहा कि लगातार जमीन की उपलब्धता कम हो रही है और निर्माण लागत बढ़ रही है। ऐसे में बढ़ती आबादी की जरूरतों के अनुरूप मास हाउसिंग,बेहतर इकोसिस्टम, लागत में कमी और निर्मित भवनों व सड़कों की उम्र बढ़ाने की दिशा में काम करना आवश्यक है।भारत सरकार के प्रतिनिधि पंकज गुप्त ने आबादी की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप तेजी से भवन निर्माण की तकनीकों और उनकी दक्षता की जानकारी अभियंताओं को दी।कार्यक्रम का संचालन अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ ने किया।इस



अवसर पर नगर निगम के मुख्य अभियंता पुनीत ओझा, भारत सरकार के प्रतिनिधि राधाकृष्ण,सहायक अभियंता दीपांकर सिंह, राजपति यादव सहित नगर निगम,विकास प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं ने प्रशिक्षण में भाग लिया और नई निर्माण तकनीकों की जानकारी हासिल की।के बजाय व्यवहार में साबित करने की जरूरत है।

संपादकीय

मजबूरियों का गठबंधन

यह एक राजनीति संभावनाओं का खेल है। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की वापसी को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। छह साल की दूरी के बाद, दोनों पार्टियों ने अपने मतभेदों को भुलाकर फिर से हाथ मिलाने का फैसला किया है।भारत यात्रा गाइड उनका यह फैसला वैचारिक समानता से कहीं अधिक राजनीतिक जरूरत को स्वीकार करने जैसा है। दोनों को समझ आ गया है कि अलग–अलग चुनाव लड़ने पर पंजाब में उनका राजनीतिक भविष्य शायद ही बच पाए। पारंपरिक रूप से, पंजाब दो–दलीय राज्य रहा है, जहाँ कांग्रेस और अकाली दल बारी–बारी से सत्ता में आते रहे हैं। पाँच साल पहले आम आदमी पार्टी के आने से यह व्यवस्था बदल गई। उसने विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की और दोनों पारंपरिक पार्टियों को हाशिए पर धकेल दिया। हालाँकि, दिल्ली में आप की कमजोर होती स्थिति और हरियाणा में मतदाताओं का भरोसा जीतने में उसकी विफलता का असर पंजाब में भी पड़ा है, जहाँ अब उसे बढ़ती राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, कांग्रेस के लिए उत्साहजनक स्थिति है। उसकी बढ़ती लोकप्रियता और राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता अन्य पार्टियों के लिए चिंता का विषय बन गई है। उन्हें डर है कि फिर से मजबूत हो रही कांग्रेस अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पा सकती है। इसलिए, अकाली दल और बीजेपी के बीच हुए इस समझौते को कांग्रेस को सत्ता में लौटने से रोकने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। हालाँकि, जिन परिस्थितियों के कारण पहले इन सहयोगियों के बीच दरार आई थी, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानून पंजाब में एक बड़ा मुद्दा बन गए थे। अकाली दल, जिसने शुरुआत में संसद में इन कानूनों का समर्थन किया था, उसे सितंबर 2020 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (छक।) से अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा, जब किसानों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए उसे ठश्रच से दूरी बनानी पड़ी। छह साल बाद भी, उनके बीच के बुनियादी मतभेद पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि पंजाब का आम किसान उस दौर की कड़वाहट को भूल गया है या इस गठबंधन का समर्थन करने के लिए तैयार है। किसानों के हित, न्यूनतम समर्थन मूल्य और आंदोलन को राजनीतिक रूप से संभालने जैसे मुद्दों को सिर्फ एक गठबंधन की घोषणा करके खत्म नहीं किया जा सकता। साथ ही, बीजेपी की स्थिति भी अभी बहुत मजबूत नहीं है। पड़ोसी राज्य राजस्थान में हाल ही में हुए पंचायत चुनावों के नतीजे यह याद दिलाते हैं कि चुनावी सफलता को पक्का मानकर नहीं चला जा सकता। पंजाब, अपने अलग राजनीतिक और कृषि–आधारित स्वरूप के कारण, कहीं अधिक जटिल चुनौती पेश करता है। हो सकता है कि दोनों पार्टियां अकाली दल को मुख्य साझेदार मानते हुए साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमत हो गई हों, लेकिन चुनावी समझौते का मतलब यह नहीं है कि जनता भी उन्हें स्वीकार कर लेगी। दो कमजोर पार्टियों द्वारा किसी साझा बड़े नुकसान से बचने की कोशिश के रूप में देखा जाना चाहिए। मतदाता उन्हें बचा पाएंगे या नहीं, यह तो एक अलग ही बात है।

हमारे संविधान को मजबूत करने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता

संजय

26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने हमारे संविधान को अपनाया। आज हम डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य को याद करते हैं। उनकी महानता इस बात में थी कि उन्होंने आधुनिक संविधान तैयार करते समय भारत की समृद्ध परंपराओं और सभ्यतागत ज्ञान से भरपूर प्रेरणा ली। भारत जैसे विविधतापूर्ण राष्ट्र के लिए, जहाँ अनेक धर्म, भाषाएँ, रीति–रिवाज और विचारधाराएँ मौजूद हैं, यह महत्वपूर्ण है कि संविधान का प्रभाव केवल संसद और अदालतों तक ही सीमित न रहे। हमारा प्रयास यह रहा है कि संविधान का जुड़ाव हमारे लोगों, विशेषकर युवाओं की सामूहिक चेतना के साथ और गहरा हो, और भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए आवश्यक एकता की भावना और मजबूत हो। यही कारण है कि एक दशक से भी अधिक समय पहले, हमारी सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। मेरे सहित करोड़ों भारतीयों के लिए, भारत का संविधान हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जब भी मैं अपने बचपन को याद करता हूँ – वे साधारण परिस्थितियाँ जिनमें मैं पला–बढ़ा और वे संघर्ष जो मेरे दैनिक जीवन का हिस्सा थे–तो मेरा मन हमारे संविधान के प्रति गहरी कृतज्ञता से भर जाता है। एक साधारण परिवार में जन्मा बच्चा, जिसे जन्म से कोई विशेष सुविधा या लाभ नहीं मिला था, वह एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सेवा करने की जिम्मेदारी संभाल सकता हैकृयह इस बात का बड़ा प्रमाण है कि हमारा संविधान कितना असाधारण है। यह हमारे संविधान की ही देन है कि अब किसी व्यक्ति के जन्म की परिस्थितियाँ उसके भविष्य की सीमाओं को तय नहीं करतीं। हमने अपने संविधान को मजबूत करके, कृतज्ञता के इस ऋण को चुकाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। संविधान के जाने–माने विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन ने हमारे संविधान को सबसे पहले एक सामाजिक दस्तावेज बताया था। सामाजिक और आर्थिक न्याय की खोज इसके ताने–बाने में रची–बसी है। ऐसे में, हमारे संविधान निर्माताओं के इस प्रिय सपने को साकार करने की दिशा में काम करने से अधिक संतोषजनक और क्या हो सकता है? विश्व बैंक की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि लगभग 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आ चुके हैं। पीढ़ियों से चले आ रहे अभावों से मुक्त होकर, अब करोड़ों माता–पिता अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य का सपना देख सकते हैं। जब प्रधानमंत्री आवास योजना यह सुनिश्चित करती है कि कोई परिवार फूस की छत वाले घर से निकलकर पक्के घर में रहे, तो गरिमा के संवैधानिक वादे को वास्तविक अर्थ मिलता है। जब उज्ज्वला योजना किसी माँ को धुएं से भरी रसोई की कठिनाइयों से मुक्त करती है, तो हम समानता और कल्याण के आदर्शों को आगे बढ़ाते हैं। जब आयुष्मान भारत किसी गरीब परिवार को कर्ज के डर के बिना अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ पाने में सक्षम बनाता है, तो सामाजिक न्याय एक हकीकत बन जाता है। जब मुद्रा और पीएम–स्वनिधि छोटे उद्यमियों और रेहड़ी–पटरी वालों को बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराते हैं, तो आर्थिक न्याय साकार होता है। जब डिजिटल तकनीक और यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म सभी तरह के भेदभावों को मिटाकर, उन अवसरों को हर नागरिक की पहुँच में ला देते हैं जो पहले केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित थे, तो हम समावेशिता के संवैधानिक आदर्श को आगे बढ़ाते हैं। हमने जो संशोधन किए हैं, उन्हें भी इसी नजरिए से देखा जा सकता है। 101वें संशोधन के जरिए ळैज् लागू हुआ, जो लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार था। 102वें संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, जिससे समाज के वंचित वर्गों का एक पुराना सपना पूरा हुआ। 103वें संशोधन को व्यापक सामाजिक स्वीकृति

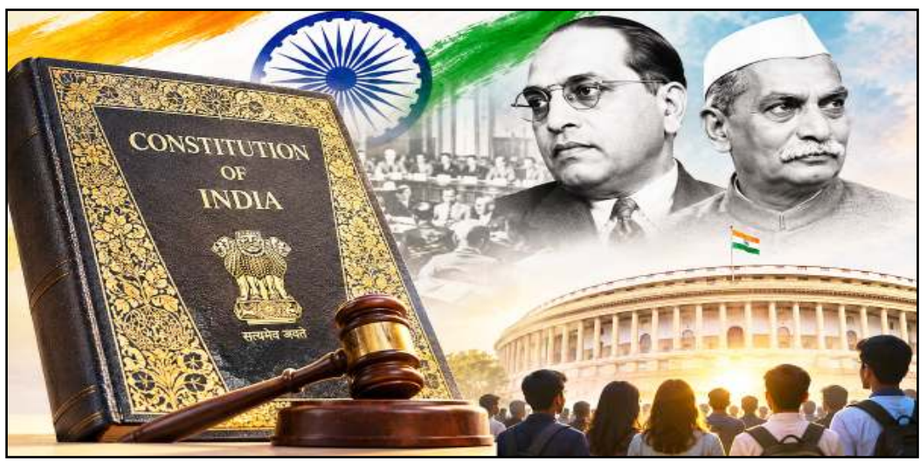

मिली। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देकर, इसने उन परिवारों की लंबे समय से अनदेखी की गई आकांक्षाओं को पूरा किया, जो मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के दायरे से बाहर थे। 1950 के बाद पहली बार, हमारे संविधान का अद्यतन संस्करण अब आठवीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे यह लोगों के और करीब आ गया है। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी, हम 1860 के दशक के औपनिवेशिक दंड संहिता के तहत ही शासित होते रहे। भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से, हमने अपनी आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बुनियादी बदलाव लाने का प्रयास किया है–जिसमें औपनिवेशिक काल के दंड पर केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर, नागरिकों पर केंद्रित श्न्यायश की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। पिछले एक दशक में, हमने कर्तव्य यानी नागरिकों के दायित्वों पर विशेष जोर दिया है। हमारी सभ्यता ने हमेशा उन जिम्मेदारियों पर बल दिया है जो समाज में हर भूमिका के साथ जुड़ी होती हैं। कर्तव्य की भावना कई जन–आंदोलनों में देखने को मिली है – स्वच्छ भारत से लेकर जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा तक।

संवैधानिक संशोधन और आपातकाल

हालाँकि, एक और सच्चाई है जिसे साझा करना मुझे जरूरी लगता है। हमारे इतिहास में ऐसे मौके आए हैं जब जिन लोगों पर संविधान को बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही इसे कमजोर करने का काम किया। विडंबना यह है कि ये वही लोग हैं जिन्हें पाँच दशकों तक भारत पर शासन करने का मौका मिला था। इस साल 1951 के पहले संविधान संशोधन को 75 साल पूरे हो रहे हैं। उस समय, एक ऐसी सरकार ने – जिसे जनता ने चुनकर नहीं भेजा था – अंतरिम संसद में अपने बहुमत का इस्तेमाल करके लोगों की बुनियादी आजादी को सीमित कर दिया था। यह संशोधन भारत के पहले आम चुनाव से कुछ ही महीने पहले लाया गया था, जो साबित करता है कि इसका मकसद चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करना और जनता के विरोध को दबाना था। इसके अलावा, आपातकाल के दौरान हुए 42वें संविधान संशोधन को भी 50 साल पूरे हो गए हैं। इस संशोधन ने न्यायिक समीक्षा (जुडिशियल रिव्यू) को सीमित कर दिया और संवैधानिक संस्थाओं की शक्तियों के संतुलन को पूरी तरह से बदल दिया। मैं युवाओं से यह भी कहूँगा कि वे 38वें और 39वें संविधान संशोधनों का अध्ययन करें, ताकि उन्हें पता चल सके कि सत्ता की भूखी और संविधान–विरोधी नेतृत्व क्या कुछ कर सकती है। भारत यात्रा गाइड चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 का बार–बार दुरुपयोग किया जाना एक और चिंताजनक अध्याय है। एक पार्टी के नाम अनुच्छेद 356 को लगभग सौ बार लागू करने का शर्मनाक रिकॉर्ड है, और एक पूर्व प्रधानमंत्री ने तो इस मामले में अर्धशतक ही लगा दिया था। हमारे संविधान निर्माताओं को उम्मीद थी कि पूरे भारत में संविधान को उसकी मूल भावना के साथ लागू किया जाएगा। लेकिन, 70 से ज़्यादा सालों तक अनुच्छेद 370 और 35 ए की वजह से जम्मू–कश्मीर में पूरा संविधान लागू नहीं हो पाया, जिससे SC, ST, OBC और महिलाओं के अधिकारों का हनन हुआ। 2019 में जाकर ही इस ऐतिहासिक गलती को सुधारा जा सका। कई दशकों तक, भारत के कुछ हिस्सों में – खासकर आदिवासी इलाकों में – नक्सलियों ने बंदूक के जोर पर सबसे गरीब लोगों को उनके वे अधिकार नहीं मिलने दिए, जो हमारे संविधान ने उन्हें दिए थे। इस साल नक्सलवाद का सफलतापूर्वक खात्मा होना बहुत सुकून देने वाली बात है, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि अब सबसे गरीब लोग भी बिना किसी डर के अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास केवल दिमागी नक्सल बचे हैं, जो आज के समय की वास्तविकताओं से कोसों दूर हैं, लेकिन हमारी विकास यात्रा को पटरी से उतारने की कोशिशों में लगातार लगे हुए हैं। यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी व्ठ आरक्षण को कम करके मुस्लिम आरक्षण लाना चाहती है। हमारे संविधान के निर्माताओं, विशेष रूप से डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर, ने इसका कड़ा विरोध किया था। हमारे संविधान का सफर उन असाधारण महिलाओं को याद किए बिना अधूरा रहेगा, जिन्होंने इसे आकार देने में मदद की। लेकिन इस साल की शुरुआत में जो हुआ, वह हम सभी के लिए शर्म की बात है। विधायी निकायों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने वाले एक कानून को विपक्ष की एक पार्टी ने पारित नहीं होने दिया। इससे एक बार फिर पता चलता है कि वे संवैधानिक मूल्यों का कितना अनादर करते हैं। मैं भारत की नारी शक्ति को विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी ताकत उन्हें न्याय मिलने से नहीं रोक सकती। हमारे संवैधानिक लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका स्पष्ट रूप से तय है। दुख की बात है कि मुख्य विपक्षी पार्टी अब एक विरोध पक्ष (विपक्ष) के बजाय एक अवरोध पक्ष (बाधा डालने वाली पार्टी) बन गई है। उन्हें यह समझना चाहिए कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बाधा डालना, संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने का विकल्प नहीं हो सकता। आज भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।

2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए, दो सरल लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत हमारे सामूहिक प्रयासों का मार्गदर्शन कर सकते हैं हमारी सोच में भारत सर्वोपरि हो और हमारे कार्यों में कर्तव्य की भावना हो। इन सिद्धांतों को अपनाकर और संविधान को अपनी ताकत का स्रोत मानकर, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

सार्थक की सार्थक पहल

आदित्य

लाखों का वेतनमान और सरकारी नौकरी के तहत मिलने वाली तमाम सुविधाएं उठाकर चंद घंटे काम करने वाले चुनाव आयोग के अधिकारी और तकनीकी जानकार जो काम नहीं कर सके, उसे एक 18 साल के लड़के ने संभव कर दिखाया है। यह काम है लाखों–करोड़ों नाम वाली वोटर लिस्ट में अपना नाम ढूंढने की तकनीकी सुविधा। अमूमन वोटर लिस्ट की लाखों पन्नों वाली स्कैन पीडीएफ फाइलों में एक नाम खोजने के लिए लोगों को घंटों मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन अब रांची के 18 साल के एथिकल हैकर सार्थक सिद्धांत ने उत्तर प्रदेश की 6.8 लाख पीडीएफ फाइलों को डिजिटल डेटा में बदलकर इसे आसानी से खंगालने वाला बना दिया है।वोटर गाइड देखें मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सार्थक ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने चुनाव आयोग की ओर से जारी उत्तर प्रदेश की सभी वोटर लिस्ट की पीडीएफ पर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर) तकनीक का इस्तेमाल किया। इससे स्कैन की गई फाइलों में मौजूद नाम और दूसरी जानकारियां मशीन से पढ़े जा सकने वाले डेटा में बदल गईं। सार्थक के मुताबिक सार्वजनिक रूप से डाउनलोड किए जा सकने वाले डेटा में निजता का भी ध्यान रखा गया है। इसमें वोटर के नाम, रिश्तेदारों के नाम, एपिक नंबर और मकान नंबर जैसे संवेदनशील पहचान संबंधी विवरणों को एक टोकन से बदल दिया गया है। दरअसल अब तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ज्यादातर वोटर लिस्ट पीडीएफ के रूप में थीं। ऐसे में किसी शख्स का नाम तलाशने के लिए पहले विधानसभा क्षेत्र और पोलिंग बूथ की जानकारी जुटानी पड़ती थी। इसके बाद उससे जुड़ी पीडीएफ डाउनलोड कर उसके पन्नों को एक–एक करके देखना होता था। ओसीआर तकनीक की मदद से अब इन फाइलों का डेटा टेबल के रूप में व्यवस्थित कर दिया गया है। इससे किसी खास रिकॉर्ड को खोजना और अलग–अलग चुनावों या रिवीजन के दौरान वोटर लिस्ट में हुए बदलावों की तुलना करना आसान होगा। सार्थक के मुताबिक अब राज्य की 403 विधानसभा सीटों के 54.8 करोड़ वोटर रिकॉर्ड्स को आसानी से खंगाला जा सकेगा। दरअसल विपक्ष चुनाव आयोग से इस तरह की व्यवस्था की मांग पहले से करता रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने 17 नवंबर को 2027 की ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट में जानकारी खोजने और डाउनलोड करने लायक पीडीएफ फाइलें उपलब्ध कराई थीं। हालांकि, सार्थक ने इससे आगे का भी काम किया है। उन्होंने मतदाता सूची के चार सेट्स को एक साथ लाकर लाखों डॉक्यूमेंट्स को एक डाटासेट बनाया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस काम के लिए सार्थक सिद्धांत की प्रशंसा करते हुए लिखा कि सार्थक का यह काम लंबा और कठिन जरूर है, लेकिन बेहद आवश्यक है। गोगोई के अनुसार, जब नागरिक सतर्क रहते हैं और जनता की सेवा के लिए बने संस्थानों की जांच–पड़ताल होती है, तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। कांग्रेस सांसद के अलावा भी कई और लोगों ने सार्थक सिद्धांत के काम को जरूरी और सराहनीय बताया है। हालांकि अब तक भाजपा या चुनाव आयोग की तरफ से सार्थक की तारीफ में कोई बयान पढ़ने नहीं मिला है। हो सकता है उन्हें लाखों लोगों की मुश्किल आसान करने वाले इस काम में कोई खासियत नजर नहीं आई हो। खैर सार्थक का यह पहला कारनामा नहीं है। हाल ही में टाइम पत्रिका ने उन्हें सौ प्रतिभाशाली भारतीय युवाओं में शुमार किया है। पत्रिका हर साल ऐसे 100 उभरते भारतीय युवाओं की सूची जारी करती है, जो अपने काम, नए आइडिया और उपलब्धियों से देश का भविष्य गढ़ने में भूमिका निभा रहे हैं। दरअसल मई महीने में सार्थक सिद्धांत तब सुर्खियों में आए थे, जब उन्होंने सीबीएसई की ऑन–स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सिस्टम में गड़बड़ियों को उजागर किया था।

रणनीतिक कंप्यूटिंग के लिए भारत की लड़ाई

विनोद

रणनीतिक कंप्यूटिंग के लिए भारत की लड़ाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दौड़ में, नुस्खा जानने से ज़्यादा जरूरी ईंधन पर नियंत्रण रखना है। भारत को दोनों की जरूरत है। पुराने जमाने के भारतीय परिवार सिलेंडर के इंतजार को याद करते हैं। माताएँ नुस्खे याद रखती थीं और मसाले स्टील के डिब्बों में रखती थीं, फिर भी रात का खाना उस लाल सिलेंडर पर निर्भर करता था जो एजेंसी के मनचाहे समय पर आता था। कौशल हमारा था, आपूर्ति नहीं।भारत यात्रा गाइड कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब अपने सिलेंडर वाले मुकाम पर पहुँच चुकी है। तीन साल तक ध्यान चतुर चौटबॉट और बेंचमार्क स्कोर पर केंद्रित रहा। अब शक्ति उसी के हाथ में है जो ईंधन को नियंत्रित करता है उन्नत चिप्स, बिजली, डेटा सेंटर और, तेजी से, इन्हें खरीदने की अनुमति। दिसंबर 2025 में, राष्ट्रपति ट्रम्प ने घोषणा की कि एनवीडिया अपना भ्200 प्रोसेसर चीन को बेच सकती है, जो एक चौंकाने वाली छूट थी। इस साल 31 मई को, वाणिज्य विभाग ने स्पष्ट किया कि लाइसेंसिंग नियम चीन में मुख्यालय वाली किसी भी कंपनी पर लागू होते हैं, जिसमें मलेशिया जैसे स्थानों पर सहायक कंपनियाँ भी शामिल हैं। बीजिंग ने तब से अपनी चाल चली है। 5 नवंबर को रॉयटर्स ने बताया कि हांगकांग में लगभग 6 लाख भ्200 सेमीकंडक्टर फंसे हुए हैं, जो मुख्य भूमि चीन से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मंजूरी नहीं मिली है, क्योंकि चीनी कंपनियां घरेलू विकल्पों की ओर रुख कर रही हैं। अब दोनों तरफ से दरवाजे खुल रहे हैं। सेमीकंडक्टर राजनीतिक दांव–पेच का जरिया बन गए हैं, जिन्हें युद्धकाल में चीनी की तरह राशनिंग करके बेचा जा रहा है। इससे भारत की स्थिति क्या है? संशयवादियों के अनुमान से कहीं आगे, हालांकि अभी भी विकास के चरम पर नहीं। जून तक, इंडियाएआई मिशन ने साझा उपयोग के लिए 45,000 से अधिक जीपीयू एकत्रित कर लिए थे। अप्रैल तक, 75 संस्थानों ने 211 चिप डिजाइन तैयार किए थेय सात चिपों का निर्माण हो चुका है, वो भी 12 नैनोमीटर जितने छोटे नोड्स पर।भारत यात्रा गाइड जुलाई में सरकार ने अपने सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए 1,27,500 करोड़ रुपये मंजूर किए। फरवरी में नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में, भारत पैक्स सिलिका में भी शामिल हुआ, जो सिलिकॉन सोर्सिंग सुरक्षित करने के लिए वाशिंगटन और उसके सहयोगियों के साथ समन्वय करने वाला एक गठबंधन है। सराहनीय प्रगति। लेकिन अंदर चल रहे एक्सीलरेटर आयातित हैं। हमने एक बढ़िया रसोईघर बनाया है और आग किराए पर ली है। तीन कार्यों को तत्काल करने की आवश्यकता है। पहला, कंप्यूटर को एक रणनीतिक भंडार के रूप में मानें, ठीक उसी तरह जैसे हम कच्चे तेल का भंडारण करते हैं। जिस राष्ट्र को अपनी प्रसंस्करण क्षमता का पूरा भरोसा नहीं है, वह आधार से जुड़ी सेवाओं से लेकर यूपीआई भुगतान तक, अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की गारंटी नहीं दे सकता। दूसरा, किसी एक पक्ष को चुनने से बचें। मध्यम शक्तियां एक साथ कई राजधानियों पर निर्भर रहकर लाभ उठाती हैं। हमारे आईटी क्षेत्र ने इसी तरह वैश्विक विश्वास अर्जित किया है, बिना किसी का उपग्रह बने हर महाद्वीप को सेवाएं प्रदान की हैं। तीसरा, और बोर्डरूम को इस पर ध्यान देना चाहिए, कंपनियों को एआई को एक और सॉफ्टवेयर सदस्यता की तरह नहीं देखना चाहिए। यदि वाशिंगटन या बीजिंग से आने वाले हर ज्ञापन के साथ चिप तक पहुंच बदलती रहती है, तो एआई रोडमैप में भू–राजनीतिक जोखिम उतना ही अधिक है जितना लाल सागर से गुजरने वाले जहाजरानी मार्ग में होता है। माल ढुलाई और डीजल के लिए आपूर्तिकर्ता जोखिम का आकलन करने वाले नेताओं को अब एल्गोरिदम के लिए भी इसका आकलन करना होगा। कौन से मॉडल किसके सर्वर पर हैं, और किस अधिकार क्षेत्र में? उन्हें कौन बंद कर सकता है? यदि कीमतें रातोंरात दोगुनी हो जाती हैं तो ग्राहक संचालन पर क्या असर पड़ेगा? प्रतिभा हमारी बाधा नहीं हैय इंजीनियर, डेटासेट और महत्वाकांक्षा प्रचुर मात्रा में हैं। कठिन प्रश्न यह है कि क्या हम अपनी शर्तों पर खाना पकाने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर पाएंगे। अनुभवी गृहिणियां कभी भी अकेले सिलेंडर पर भरोसा नहीं करती थीं। वे काउंटर के नीचे एक अतिरिक्त सिलेंडर रखती थीं, क्योंकि लंबे इंतजार ने उन्हें सिखाया था कि डिलीवरी कैसे होती है। नीति निर्माताओं और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस ज्ञान को अपनाना चाहिए। कोई नुस्खा, चाहे कितना भी शानदार क्यों न हो, तब तक किसी को लाभ नहीं पहुंचाता जब तक कि उसे लागू न किया जाए।

कमोडिटी बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली

अजय

इस साल के ज़्यादातर समय कमोडिटी बाजार भू–राजनीतिक हालात से प्रभावित रहे। सैन्य कार्रवाई, सप्लाई चेन में रुकावट, महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदों के चलते कमोडिटी की कीमतें अभूतपूर्व स्तर तक पहुँच गई थीं। हालाँकि, हाल के दिनों में कमोडिटी बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली है, जिससे लगता है कि तेजी का यह दौर अब खत्म हो गया है। एनर्जी प्रोडक्ट्स (कच्चा तेल), इंडस्ट्रियल मेटल्स (तांबा और एल्युमीनियम) और कीमती धातुओं (सोना और चांदी) की कीमतों में भारी गिरावट आई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सप्लाई चेन की रुकावटें काफी हद तक कम हो गई हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य से आवाजाही तेजी से सामान्य हो रही है। साथ ही, केंद्रीय बैंक महंगाई को काबू करने के लिए लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं और बाजार में लिक्विडिटी (नकदी) को कम कर रहे हैं। हालाँकि भू–राजनीतिक जोखिम पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन बाजार के जानकारों को फिलहाल इनके और बढ़ने की उम्मीद नहीं है। रिपोर्टों के अनुसार, जहाजों पर छिटपुट हमलों के बावजूद खाड़ी



देशों से निर्यात एक उच्च स्तर पर स्थिर हो गया है और अब युद्ध–पूर्व के स्तर के लगभग 80% तक पहुँच गया है। तनाव कम होने से वॉर रिस्क प्रीमियम में भी कमी आई है। हाल तक कच्चे तेल सहित कई प्रमुख कमोडिटीज की कीमतों में यह प्रीमियम शामिल था। पिछले शुक्रवार तक ब्रेंट क्रूड लगभग 92 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, और साल के अंत तक इसमें 5: की गिरावट आने की संभावना है। यूरोपीय गैस बाजार में कीमतें दबाव में हैं, जबकि अमेरिका में हल्की सर्दी के पूर्वानुमान के कारण गैस की मांग कम हो सकती है।

तांबे की बात करें तो, 14,800 डॉलर प्रति टन के उच्च स्तर से गिरकर इसकी कीमत लगभग 12,500 डॉलर प्रति टन पर आ गई है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद (अगली फेड बैठक 8 दिसंबर को है) का असर इस इंडस्ट्रियल मेटल पर पड़ रहा है। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रेरित मांग में तेजी कब तक बनी रहेगी, इसे लेकर भी संदेह है। साथ ही, रिफाइंड तांबे पर अमेरिकी आयात शुल्क (लगने की उम्मीदें भी कम हो गई हैं। चीन को लेकर चिंताएं भी इंडस्ट्रियल मेटल्स पर दबाव बढ़ा रही हैं। एल्युमीनियम की कीमतें भी दबाव में हैं और पिछले एक महीने में लगभग 5: गिरकर 2,870 डॉलर प्रति टन पर आ गई हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य में हालात सुधरने से इस क्षेत्र में उत्पादन की संभावनाएं बेहतर हुई हैं। इस साल सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी देखी गई और इनकी कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गईं, लेकिन हाल के हफ्तों में अमेरिकी बॉन्ड यील्ड के ऊंचे स्तर और डॉलर के मजबूत होने के कारण इनकी कीमतों में भारी गिरावट आई है। 20 नवंबर को, एक ट्रॉय औंस सोने की कीमत 3,572 डॉलर थी। यह एक महीने पहले की तुलना में 20: और एक साल पहले के स्तर से 13: नीचे आ गई है। चूंकि सोने से कोई निश्चित रिटर्न (यील्ड) नहीं मिलता, इसलिए जब अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ऊंचे बने रहेकृखासकर दिसंबर की बैठक में फेड द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की संभावना के बीचकृऔर भू–राजनीतिक तनाव कम होने लगे, तो सोने की कीमतों में गिरावट आ गई। एक कीमती धातु होने के साथ–साथ, चांदी की औद्योगिक मांग भी होती है। हालांकि, सोलर पैनल सेक्टर से इसकी मांग कमजोर होने लगी है, क्योंकि उपयोगकर्ता अब अधिक स्थिर और कम उतार–चढ़ाव वाले विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। पिछले सप्ताहांत, चांदी की कीमत 41 डॉलर प्रति औंस से थोड़ी ऊपर थी। प्लैटिनम भी धातुओं की बिकवाली की चपेट में आ गया है। इसकी कीमत गिरकर 1,300 डॉलर प्रति औंस हो गई है, जो अगस्त 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर है। आभूषणों की मांग में कमी के कारण प्लैटिनम बाजार में अब सरप्लस की स्थिति बन गई है। यह स्पष्ट है कि भू–राजनीतिक कारणों से कीमतों में जो उछाल आया थाकृजिसने कुछ कमोडिटीज की कीमतों को बहुत ऊपर पहुंचा दिया थाकृवह अब खत्म हो चुका है। जैसे–जैसे तनाव कम हो रहा है और आपूर्ति सामान्य हो रही है, प्रमुख कमोडिटीज के लिए आपूर्ति और मांग के बुनियादी कारक (फंडामेंटल्स) फिर से प्रभावी होने लगे हैं। बाजार में जोखिम लेने की इच्छा (रिस्क एपेटाइट) कम हो रही है। ऐसी व्यापक उम्मीद है कि 2027 में भू–राजनीतिक मुद्दे पीछे छूट जाएंगे, ऊर्जा की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी, महंगाई में कमी आएगी, आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और बाजारों में उतार–चढ़ाव कम होगा। ऐसी स्थिति में, प्रमुख औद्योगिक कमोडिटीज की मांग मजबूत होने लगेगी। इसलिए, 2027 में प्रमुख कमोडिटीज के लिए दृष्टिकोण कुल मिलाकर सकारात्मक है। बाजार में उतार–चढ़ाव अलग–अलग कमोडिटीज की अपनी विशिष्ट स्थितियों और कारकों पर निर्भर करेगा।

मतदाता पुनरीक्षण अभियान का जायजा लेने जौनपुर आएंगे विशेष कार्याधिकारी शिव प्रताप शुक्ल

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अर्हता तिथि एक जनवरी 2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम–2027 के तहत 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान जनपद के सभी मतदेय स्थलों (बूथों) पर व्यवस्थाओं और बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के विशेष कार्याधिकारी शिव प्रताप शुक्ल जौनपुर का भ्रमण करेंगे। विशेष अभियान दिवसों पर बीएलओ की उपस्थिति, मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित कार्यों और बूथों पर की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण एवं आकलन किया जाएगा। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों और बीएलओ को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित मतदेय स्थलों पर समय से उपस्थित रहें तथा निरीक्षण के दौरान आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करें।

मारपीट और लूटपाट में नौ लोगों पर मुकदमा

जौनपुर । रामपुर थाना क्षेत्र के आशानंदपुर गांव में एक लाख रुपए की रंगदारी मांगने और रकम न देने पर घर में घुसकर मारपीट व लूटपाट करने के आरोप में नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।गांव के प्रभात तिवारी का आरोप है कि 2 अक्टूबर 2026 की शाम करीब 6 बजे गांव के कुछ लोग उनके दरवाजे पर पहुंचे और एक लाख रुपए मांगे। रुपए न होने की बात कहने पर आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट और गाली–गलौज की। उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी।प्रभात तिवारी के मुताबिक, आरोपी घर में रखा गद्दा, तकिया, कम्फर्टर, डबल बेड, 50 हजार रुपए नकद और सोने की चेन ले गए। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के आदेश पर विजय सिंह, विनय सिंह, अनुभव सिंह, अर्पित सिंह, उदयप्रताप सिंह, विनय कुमार, अनिल सिंह, सुनील सिंह और अन्नू के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शादी वाले परिवार में मारपीट का आरोप

जौनपुर । जलालपुर थाना क्षेत्र के बलुआ कोरी गांव में शादी वाले परिवार में पड़ोसियों पर मारपीट और महिलाओं से बदसलूकी करने का आरोप लगाया है। परिवार का आरोप है कि घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम के साथ भी कुछ लोगों ने धक्का–मुक्की और गाली–गलौज की। घटना का एक वीडियो सामने आया है। गांव निवासी महेंद्र राजभर के बेटे की शादी आगामी 2 तारीख को है। परिवार शादी की तैयारियों के लिए बाहर से गांव लौटा था। महेंद्र का आरोप है कि उनके खानदान के पड़ोसी और कुछ अन्य लोग परिवार के साथ मारपीट कर रहे हैं। महिलाओं के साथ भी बदसलूकी और मारपीट की गई। पुलिस टीम के साथ महिलाओं ने धक्का–मुक्की और गाली–गलौज की।महेंद्र ने जलालपुर थाने में तहरीर देकर सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस टीम घटनास्थल का जायजा लेने पहुंची। आरोप है कि वहां मौजूद कुछ लोगों और महिलाओं ने पुलिसकर्मियों से नोकझोंक की। उनके साथ धक्का–मुक्की और गाली–गलौज भी की गई।परिवार का कहना है कि करीब एक साल पहले भी इसी तरह के विवाद में केस दर्ज हुआ था। परिवार ने आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोग मौजूदा मामले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भविष्य में किसी बड़ी घटना की आशंका जताते हुए सुरक्षा की मांग की है।

सड़क बनने एक सप्ताह बाद खुला गुणवत्ता का पोल

जौनपुर। नगर पंचायत कजगांव के वार्ड संख्या आठ में नगर पंचायत द्वारा सीसी रोड़ बनवाया गया है। जिसका फोटो व वीडियों इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।जिसमें देख सकते हैं कि ठीक ढंग से एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि अचानक सीसी रोड़ में दरारें आ गई है।ज्ञात हो कि जिस समय इस सीसी रोड़ का निर्माण नगर पंचायत द्वारा कराया जा रहा था।उसी समय इस सीसी रोड़ के गुणवत्ता एवं मानक को लेकर लोगों ने सवाल उठा था कि यह सीसी रोड़ मानक विहीन ईंट व सामग्री लगाकर बनाया जा रहा था।और उन दिनों यह सीसी रोड़ मिडिया और सोशल मीडिया में भी इसकी खबरें जोरों पर चली थी।उसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष व स्थानीय सभासद के द्वारा मौके पर जाकर गुणवत्ता पूर्वक कार्य होने का दावा भी किया गया था।नगर पंचायत अध्यक्ष व सभासद के दावा के बाद कार्य को पूर्ण करा दिया गया।इसके के बाद इस रोड़ का हाल यह हुआ कि एक सप्ताह भी ठीक ढंग से नहीं बीता था कि यह सीसी रोड़ में जगह–जगह दरारें आना शुरू हो गया ।जब इस सीसी रोड़ का फोटो व वीडियो मीडिया व सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद इस रोड को लेकर स्थानीय सभासद ने के साथ कुछ ग्रामीणों ने यह कहा कि रोड़ में कोई अनियमितता नहीं है। ऐसी दशा में सीसी रोड़ में का फटना हुआ दरारें आना किस बात की ओर संकेत करता है।इस सीसी रोड़ को लेकर इस वार्ड के सभासद के साथ अन्य कुछ लोगों द्वारा कहा गया कि यह रोड़ मानक के अनुसार ही बन रहा है लेकिन एक सप्ताह भी नहीं बिता की जगह–जगह सड़क का फटना और दरारे आना आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहां मानक के अनुसार कार्य किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिम्मेदारों द्वारा सिर्फ खुलेआम सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा भ्रष्टाचार को जमकर बढ़ावा दिया जा रहा है।

18 वर्ष पूरे करने वाले युवा और छूटे हुए लोगों को मतदाता बनने हेतु किया गया जागरूक

युवा और महिला मतदाताओं को जोड़ने के लिए हरगोविंद इंटर कॉलेज व जीजीआईसी जफराबाद में हुआ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव



जौनपुर। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2027 के अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारीध जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के निर्देशन में चल रही स्वीप गतिविधियों की कड़ी में हरगोविंद इंटर कॉलेज और राजकीय बालिका इंटर कालेज जफराबाद में निर्वाचन साक्षरता क्लब के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र–छात्राओं को लोकतंत्र में मताधिकार के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। विशेष रूप से उन युवाओं को जागरूक किया गया जो 01 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, तथा जो पात्र होने के बावजूद अभी तक मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वा पाए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला स्वीप कोआर्डिनेटर सैय्यद मोहम्मद मुस्तफा ने मतदाता बनने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि पात्र युवा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए 'फॉर्म–6' भरकर ऑनलाइन या बीएलओ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए आयु प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। साथ ही माध्यम से भी घर बैठे आवेदन किया जा सकता है। स्वीप कोआर्डिनेटर मुस्तफा ने कहा कि 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में सभी पात्र युवा, विशेषकर युवा और महिला मतदाता अपना नाम अवश्य जुड़वाएं, ताकि ष्कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहींष के संकल्प को पूरा किया जा सके। उन्होंने छात्र–छात्राओं से अपील की कि वे स्वयं मतदाता बनें और अपने परिवार, मोहल्ले व गांव में छूटे हुए पात्र लोगों को भी मतदाता बनने के लिए प्रेरित करें। 28 व 29 नवम्बर को सभी मतदान केन्द्रों पर बीएलओ बैठेंगे। जिनके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

कार्यक्रम में छात्र–छात्राओं ने बढ़–चढ़कर भाग लिया और जिम्मेदार मतदाता बनने की शपथ ली। इस अवसर पर हरगोविंद इंटर कालेज के प्रधानाचार्य डॉ संजीव कुमार सिंह जी, जीजीआईसी प्रधानाचार्य प्रतिमा यादव, ईएलसी नोडल सै अब्बास हैदर व डॉ रोली सिन्हा, अजय कुमार, डॉ रिचा त्रिपाठी, सीमा मिश्रा आदि सहित छात्र छात्राएं उपस्थित रहीं।

राम–कृष्ण संवाद पुस्तक का विमोचन, अभिनव नाट्य प्रयोग की विद्वानों ने की सराहना

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय



लखनऊ – गोमतीनगर स्थित कबीर शांति मिशन के सभागार में मंगलवार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम और नट नागर कृष्ण के तुलनात्मक जीवन–वृत्त पर आधारित विनोद कुमार दीक्षित की सद्यः प्रकाशित पुस्तक श्राम–कृष्ण संवादश का विमोचन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी महेश चंद्र द्विवेदी ने की, जबकि संचालन कंचन शुक्ला ने किया। पुस्तक की भावभूमि पर चर्चा की शुरुआत करते हुए लेखक विनोद कुमार दीक्षित ने बताया कि इस पुस्तक के लेखन के लिए बीस से अधिक संदर्भ ग्रंथों से सामग्री संकलित की गई है। पुस्तक के प्रारंभ में दोनों विभूतियों के संबंध में विशिष्ट जानकारियां देने के साथ ही उनके तुलनात्मक जीवन को नाट्य शैली में प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के पात्र भी स्वयं राम और कृष्ण ही हैं। उन्होंने कहा कि राम और कृष्ण के बीच संवाद को नाट्य शैली में प्रस्तुत करने का प्रयोग अब तक किसी ने नहीं किया है। यह एक नितांत अभिनव प्रयास है। कार्यक्रम की अति विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डॉ. विद्या बिन्दु सिंह ने कहा कि श्री दीक्षित का यह प्रयास अत्यंत सराहनीय है। अब देखना यह है कि पाठक इस पुस्तक को किस रूप में स्वीकार करते हैं। विशिष्ट अतिथि डॉ. सुधा मिश्रा और डॉ. सुल्तान शाकिर हाश्मी ने भी श्री दीक्षित के इस अनूठे प्रयास को श्लाघनीय बताते हुए कहा कि इस प्रयोग का नयापन निश्चित रूप से पाठकों को पसंद आएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुंवर वीर सिंह मार्तण्ड ने पुस्तक की विस्तार से समीक्षा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि पुस्तक में अनेक अछूते बिंदुओं पर तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण दिया गया है, जो गहन अध्ययन और अनुसंधान का परिणाम है। दीक्षित जी का यह प्रयोग सराहनीय तो है ही, साथ ही भावी लेखकों के लिए शोध–सामग्री के रूप में भी उपयोगी सिद्ध होगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं पूर्व डीजीपी महेश चंद्र द्विवेदी ने अपने सारगर्भित संबोधन में कहा कि विषय आसान नहीं था। अनेक विवादित तथ्यों को समेकित कर प्रस्तुत करना अत्यंत दुरूह कार्य था, लेकिन श्री दीक्षित ने बड़ी कुशलता से इन विवादों के बीच जो तादात्म्य स्थापित किया है, वह उनकी अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति का परिचायक है। उन्होंने कहा कि श्री दीक्षित ने एक शाश्वत और अभिनव प्रयोग के माध्यम से न केवल साहित्य को समृद्ध किया है, बल्कि एक नई लकीर भी खींची है। अंत में लेखक विनोद कुमार दीक्षित ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को निःशुल्क पुस्तक भेंट की तथा सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया।

सर्दियों में हादसों का बढ़ता खतरा, समय पर इमरजेंसी उपचार से बच सकती है जान – मेदांता लखनऊ

मेदांता लखनऊ के विशेषज्ञों ने दी हादसों से बचाव की सलाह, बताया गोल्डन आवर में उपचार का महत्व

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय



लखनऊ। सर्दियों का मौसम गुनगुनी धूप के साथ हादसों का खतरा भी लेकर आता है। घने कोहरे, सड़कों पर नमी और कम दृश्यता के कारण सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा घरों में फिसलकर गिरने जैसी घटनाएं भी गंभीर चोटों का कारण बन सकती हैं। ऐसे मामलों में समय पर जांच और उचित उपचार मरीज की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सर्दियों में होने वाले हादसों से बचाव और समय पर उपचार के महत्व को लेकर मेदांता अस्पताल, लखनऊ के विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस अवसर पर डॉ. राकेश कपूर, मेडिकल डायरेक्टरय डॉ. कमलेश सिंह भैसोरा, डायरेक्टर, न्यूरोसर्जरीय डॉ. रवि शंकर, डायरेक्टर, न्यूरोसर्जरीय डॉ. लोकेन्द्र गुप्ता, डायरेक्टर, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा सेंटरय डॉ. सौरव शुक्ला, डायरेक्टर, ऑर्थोपेडिक्सय डॉ. सैफ एन शाह, डायरेक्टर, ऑर्थोपेडिक्स और डॉ. धर्मेंद्र सिंह, डायरेक्टर, ऑर्थोपेडिक्स मौजूद रहे। विशेषज्ञों ने बताया कि घने कोहरे में दृश्यता कम होने के कारण हाईवे और एक्सप्रेसवे पर वाहनों की टक्कर का खतरा बढ़ जाता है। वहीं, सुबह के समय सड़कों पर ओस और नमी के कारण दोपहिया वाहनों के फिसलने की आशंका रहती है। तेज रफ्तार और हेलमेट का उपयोग न करने से सिर एवं चेहरे पर गंभीर चोट लगने का जोखिम बढ़ जाता है। मेदांता लखनऊ के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. राकेश कपूर ने बताया कि गंभीर चोट के मामलों में शुरुआती जांच और चोट की सही पहचान बेहद जरूरी है। कई बार मरीज बाहरी तौर पर सामान्य दिखाई देता है, जबकि उसके पेट, छाती या मस्तिष्क में अंदरूनी रक्तस्राव या रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में मरीज की स्थिति अचानक बिगड़ सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2024' के अनुसार, वर्ष 2024 में देशभर में कोहरे और धुंध के दौरान 33,955 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें 15,115 लोगों की मौत हुई और 29,827 लोग घायल हुए। वहीं, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 के दौरान सभी मौसमों में हुई 46,052 सड़क दुर्घटनाओं में 24,118 लोगों की जान गई। विशेषज्ञों के अनुसार, किसी गंभीर हादसे के बाद का पहला घंटा, जिसे 'गोल्डन आवर' कहा जाता है, मरीज की जान बचाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे मामलों में बिना देरी किए मरीज को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है। सिर में चोट लगने के बाद बार–बार उल्टी होना, तेज सिरदर्द, अत्यधिक उनींदापन, बेहोशी, दोनों आंखों की पुतलियों के आकार में असमानता और हाथ–पैर में कमजोरी जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये मस्तिष्क में गंभीर चोट के संकेत हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। हादसों से बचाव के लिए वाहन की गति नियंत्रित रखें, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें तथा घने कोहरे में वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखें। घरों में फर्श को सूखा रखें, बुजुर्गों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। मेदांता लखनऊ के इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर में मरीज के पहुंचने पर सबसे पहले उसके श्वसन मार्ग, सांस लेने की स्थिति और रक्त परिसंचरण का आकलन किया जाता है। इसके बाद आवश्यकता के अनुसार फास्ट अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन जैसी जांचों की मदद से अंदरूनी चोटों की पहचान की जाती है। गंभीर मामलों में ट्रॉमा रिस्पॉन्स टीम और संबंधित विभागों के विशेषज्ञ मिलकर उपचार शुरू करते हैं। मेदांता लखनऊ की इमरजेंसी एवं ट्रॉमा केयर सुविधाएं, आधुनिक क्रिटिकल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुभवी विशेषज्ञों की टीम गंभीर रूप से घायल मरीजों को समय पर जांच एवं उपचार उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। विशेषज्ञों ने लोगों से सर्दियों में विशेष सावधानी बरतने और किसी भी गंभीर हादसे के बाद उपचार में देरी न करने की अपील की।

सीसी रोड़ बने हुए एक सप्ताह भी नहीं बिता कि खुल गया गुणवत्ता का पोल

सीसी रोड़ में आयी दरारें का फोटो व वीडियों सोशल मीडिया पर वायरल,लोगों में बना चर्चा का विषय

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव



जौनपुर। जनपद का बहुचर्चित नगर पंचायत कजगांव जो एक के बाद एक कारनामा करता रहता है।और अपने कारनामा के चलते हमेशा चर्चा में भी बना रहता है।प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पंचायत कजगांव के वार्ड संख्या आठ में नगर पंचायत द्वारा सीसी रोड़ बनवाया गया है। जिसका फोटो व वीडियों इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।जिसमें आप देख सकते हैं कि ठीक ढंग से एक सप्ताह भी नहीं बीता था कि अचानक सीसी रोड़ में दरारें आ गई है।आपकों बता दें कि जिस समय इस सीसी रोड़ का निर्माण नगर पंचायत द्वारा कराया जा रहा था।उसी समय इस सीसी रोड़ के गुणवत्ता एवं मानक को लेकर लोगों ने सवाल उठा था कि यह सीसी रोड़ मानक विहीन ईंट व सामग्री लगाकर बनाया जा रहा था।और उन दिनों यह सीसी रोड़ मिडिया और सोशल मीडिया में भी इसकी खबरें जोरों पर चली थी।उसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष व स्थानीय सभासद के द्वारा मौके पर जाकर गुणवत्ता पूर्वक कार्य होने का दावा भी किया गया था।नगर पंचायत अध्यक्ष व सभासद के दावा के बाद कार्य को पूर्ण करा दिया गया।इसके के बाद इस रोड़ का हाल यह हुआ कि एक सप्ताह भी ठीक ढंग से नहीं बीता था कि यह सीसी रोड़ में जगह–जगह दरारें आना शुरू हो गया ।जब इस सीसी रोड़ का फोटो व वीडियो मीडिया व सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद इस रोड को लेकर स्थानीय सभासद ने के साथ कुछ ग्रामीणों ने यह कहा कि रोड़ में कोई अनियमितता नहीं है। ऐसी दशा में सीसी रोड़ में का फटना हुआ दरारें आना किस बात की ओर संकेत करता है।इस सीसी रोड़ को लेकर इस वार्ड के सभासद के साथ अन्य कुछ लोगों द्वारा कहा गया कि यह रोड़ मानक के अनुसार ही बन रहा है लेकिन आपको बता दे की एक सप्ताह भी नहीं बिता की जगह–जगह सड़क का फटना और दरारे आना आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यहां मानक के अनुसार कार्य किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिम्मेदारों द्वारा सिर्फ खुलेआम सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा भ्रष्टाचार को जमकर बढ़ावा दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि आखिर कब तक ऐसा खेल नगर पंचायत कजगांव में चलता रहेगा।सीसी रोड़ में जगह–जगह दरारें आने के बाद भ्रष्टाचार छुपाने के लिए तमाम जगहों पर दरारें आयी थी वहां कटर मशीन लगा कर सीसी रोड़ को इस पार से लेकर उस पार तक काटा गया है।ताकि सीसी रोड़ में आयी दरारों को छुपाया जा सके। जहां एक तरफ सरकार प्रदेश में विकास करके उत्तम प्रदेश बनाने की बात करती है वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत कजगांव द्वारा सीसी रोड़ में खुलेआम मानक को ताख पर रखते हुए सरकार के मन्सा पर खुलेआम पानी फेरनें में बराबर जुटा हुआ है।

नुक्कड़ नाटक में बाल विवाह की रोकथाम का संदेश

जौनपुर अंतरराष्ट्रीय बाल विवाह उन्मूलन दिवस के अवसर पर जन विकास संस्थान एवं महिला एवं बाल कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कलेक्ट्रेट परिसर में 'चुनरी बनी परचम' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला प्रोबेशन अधिकारी विजय कुमार पाण्डेय, बाल संरक्षण अधिकारी चंदन रॉय, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य अनिल यादव ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना किया। रैली जिला प्रोबेशन कार्यालय से प्रारंभ होकर करके पूरा कलेक्ट्रेट परिसर से होते हुए शहर के सड़कों से गुजरते हुए जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष पहुंची, जहां जनसभा का आयोजन किया गया। मछलीशहर, मड़ियाहूं एवं बरसठी विकासखंडों की कुल 150 किशोरियों ने प्रतिभाग किया। जागरूकता रैली, जनसभा एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को बाल विवाह के सामाजिक, शारीरिक एवं मानसिक दुष्परिणामों तथा इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया। मुख्य अतिथि जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जिसकी रोकथाम के लिए प्रशासन के साथ–साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित विभाग अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को सूचित करें। बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों का संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी विभागों एवं सामाजिक संगठनों के समन्वित प्रयासों से जौनपुर को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में कार्य करना होगा।"

लखनऊ में कांग्रेस के संविधान रक्षा मार्च को अनुमति नहीं, फिर भी पार्टी निकालेगी खरगे करेंगे नेतृत्व

लखनऊ, (संवाददाता)।संविधान दिवस पर 26 नवंबर, बृहस्पतिवार को कांग्रेस की ओर से राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में संविधान रक्षा मार्च निकाला जाएगा। हालांकि, जिला प्रशासन ने मार्च की अनुमति नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी मार्च निकालने पर अड़ी है। पूर्व सांसद पीएल पुनिया ने बुधवार को प्रेसवार्ता में कहा कि पार्टी ने पहले ही संविधान रक्षा मार्च की घोषणा कर दी थी।



यह यात्रा सुबह 11 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय नेहरू भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शुरू होगी और एनेक्सी भवन होते हुए हजरतगंज स्थित बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर समाप्त होगी। पुनिया ने कहा, हमने शांतिपूर्ण मार्च निकालने के लिए लिखित आवेदन दिया था, फिर भी अनुमति नहीं मिली। प्रशासन ने इसे संवेदनशील क्षेत्र बताकर मार्च की अनुमति देने से इनकार किया है। यह यात्रा संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से निकाली जाएगी, जिसमें प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। इससे पहले पार्टी कार्यालय में संविधान की प्रस्तावना की शपथ ली जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष कहीं भी जा सकते हैं, किंतु हमें मार्च की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुनिया का आरोप है कि एसआईआर के जरिये लोगों के वोट का अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है, जबकि वोट का अधिकार संविधान से मिला है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहे हैं और आगे भी जारी रहेंगे। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने मार्च के लिए अनुमति न मिलने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेसजन संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के संकल्प के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

एसएन में ओपन हार्ट सर्जरी पर ब्रेक, इंतजार में 32 मरीज, नए पंजीकरण कर दिए गए बंद

आगरा, संवाददाता। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में जोर–शोर से शुरू की गई ओपन हार्ट सर्जरी की सुविधा पर फिलहाल ब्रेक लगा है। यहां पर कार्डियक एनेस्थीसियन और ईको कार्डियोग्राफी मशीन नहीं होने से ऑपरेशन नहीं हो पा रहे हैं। मरीजों की वेटिंग बढ़ती जा रही है। ऐसे में गंभीर मरीज निजी अस्पताल या दूसरे शहरों में जाने के लिए मजबूर हैं। सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक की चौथी मंजिल पर कार्डियोथोरोसिस एंड वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस) विभाग चल रहा है। इसमें ओपन हार्ट सर्जरी की भी सुविधा है। पांचवीं मंजिल पर इसके लिए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बने हैं। इसी साल 15 मई को पहली बार बाईपास सर्जरी हुई थी। अप्रैल में 13 साल के बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी की गई। सितंबर में 58 साल की महिला की ओपन हार्ट सर्जरी की गई। इसके बाद से ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो रही है। इन दो सर्जरी में एसएन के ही चिकित्सकों और कैथ लैब की मशीन का उपयोग किया गया था। अब इसमें विशेष कार्डियक एनेस्थीसियन और अलग से मशीन की जरूरत है, जिससे ऑपरेशन के बाद मरीज की बेहतर देखभाल हो सके। इनकी व्यवस्था नहीं होने से सर्जरी कराने के लिए मरीजों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता का कहना है कि एसजीपीजीआई लखनऊ में विशेषज्ञों को प्रशिक्षण के लिए भेज रहे हैं, जिससे वह इसमें महारत हासिल कर लेंगे। मशीन खरीद की प्रकिया चल रही है। सीटीवीएस की ओपीडी में रोजाना 40–50 मरीज आ रहे हैं। इनमें से 4–5 मरीजों को ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत पड़ रही है। सर्जरी के लिए अभी 32 मरीज पंजीकृत किए जा चुके हैं। सर्जरी न होने से नए पंजीकरण भी बंद हैं। सीटीवीएस विभाग के डॉ. सुशील सिंघल ने बताया कि आयुष्मान योजना और असाध्य रोग योजना में सर्जरी पूरी तरह से निशुल्क है। अन्य मरीजों के लिए करीब डेढ़ लाख रुपये का खर्चा आता है। निजी अस्पतालों में ओपन हार्ट सर्जरी का खर्चा 4–5 लाख रुपये तक है।



मेट्रो के खिलाफ भड़के शिक्षक : आगरा कॉलेज की दीवार और पट्टिका तोड़ने पर हंगामा

आगरा, संवाददाता। शिक्षकों का आरोप है कि मेट्रो की ओर से पार्किंग भी बिना अनुमति के बनाई जा रही है। इसके विरोध में एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायती पत्र दे रहे हैं। डीएम को भी इसकी जानकारी दे दी है। विरोध में शिक्षकों ने कल से धरना देने का ऐलान किया है। प्राचार्य डॉक्टर सीके गौतम ने बताया कि मेट्रो ने बिना अनुमति के ही कॉलेज के मैदान की दीवार तोड़ दी है। वहां 40 साल पुरानी लगी पट्टिका को भी तोड़ दिया। यहां पर पार्किंग भी बिना अनुमति के बनाई जा रही है। इसके विरोध में एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायती पत्र दे रहे हैं। डीएम को भी इसकी जानकारी दे दी है।

बाल्टी में डूबकर एक साल की मासूम की मौत

आगरा, संवाददाता। मौत को तो बस बहाना चाहिए...कुछ ऐसा ही बुधवार को बाह थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरा चौसिंगी गांव में दिखा। पानी से भरी बाल्टी में औंधे मुंह गिरने से एक साल की मासूम निहांशी की जान चली गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों ने करीब एक घंटे तक सीपीआर देकर बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें नहीं लौट सकीं। घटना से परिवार में मातम पसरा है। हादसा दोपहर करीब 2 बजे का है। रघुनाथपुरा चौसिंगी निवासी उमेश कुमार बटेश्वर मेले में दुकान लगाने गए थे। उनकी पत्नी नीरू एक वर्षीय बेटी निहांशी को खाट पर दूध की बोतल देकर कपड़े धोने चली गईं। बच्ची खाट से उतरकर घुटनों के बल रेंगते हुए बाथरूम तक पहुंच गई। बाथरूम के फर्श पर पानी से भरी एक बड़ी बाल्टी रखी थी। आशंका जताई जा रही है कि बच्ची ने बाल्टी पर चढ़ने या झांकने का प्रयास किया, जिससे वह संतुलन खोकर औंधे मुंह पानी में जा गिरी और बाहर नहीं निकल सकी। कुछ देर बाद जब नीरू ने खाट पर बच्ची को नहीं देखा तो वे उसे खोजते हुए बाथरूम पहुंचीं। वहां निहांशी को बाल्टी में औंधे मुंह पड़ा देख उनकी चीख निकल गई। चीखें सुनकर परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे और बच्ची को बाहर निकाला। लोगों ने उसे उल्टा लिटाकर पेट का पानी निकालने का प्रयास किया। बेहोशी की हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉ. अमन कुमार और फार्मासिस्ट मनोज शर्मा ने करीब एक घंटे तक लगातार सीपीआर दी।

संक्षिप्त खबरें

बेकाबू एसयूवी की चपेट में आने से किशोरी घायल

सुल्तानपुर, संवाददाता। अयोध्या–प्रयागराज हाईवे पर रुसहा मोड़ के पास बुधवार दोपहर तेज रफ्तार एसयूवी की चपेट में आने से ठेले पर धान लेकर जा रही मठिया रुसहा निवासी नेहा यादव (16) घायल हो गईं। इस दौरान एसयूवी भी अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। नेहा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कूरेभार से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। कूरेभार के प्रभारी थानाध्यक्ष भरत सिंह ने बताया कि एसयूवी को पुलिस ने कब्जे में लिया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी की जाएगी।

संविदा चालक–परिचालक पर सख्ती, 45 को नोटिस

सुल्तानपुर, संवाददाता। रोडवेज निगम ने संविदा चालक और परिचालकों की मनमानी पर सख्ती शुरू की है। बिना सूचना ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले 45 कर्मियों को नोटिस जारी किया गया है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेश चंद्र यादव ने बुधवार को यह नोटिस जारी किया। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनकी संविदा समाप्त करने की तैयारी है। डिपो में कर्मचारियों के मनमाने ढंग से अनुपस्थित रहने की शिकायतें थीं। अधिकारियों के अनुसार, 50 से अधिक संविदा चालक–परिचालक अक्सर बिना सूचना गैरहाजिर रहते हैं। कुछ कर्मी कई महीने से ड्यूटी पर नहीं आए हैं। कुछ लगातार चार–पांच दिन तक गायब रहते हैं। इससे बसों के संचालन की व्यवस्था भी प्रभावित होती है। निगम पहले भी संविदा चालक प्रदीप पाल की सेवा समाप्त कर चुका है।

4.45 करोड़ से छह सड़कों की बदलेगी सूरत, ग्रामीणों को मिलेगी राहत

बांदा, संवाददाता। तिंदवारी और पैलानी क्षेत्र के छह मार्गों की दशा सुधारने के लिए 4.45 करोड़ खर्च किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग की ओर से इन सड़कों पर विशेष मरम्मत, पुलिया निर्माण और रिटेनिंग वॉल के कार्य कराए जाएंगे। इससे ग्रामीणों का आवागमन आसान होगा। बारिश के दौरान सड़क कटान और जलनिकासी की समस्या से भी राहत मिलने की उम्मीद है। तिंदवारी–जौरही अन्य जिला मार्ग पर दो स्थानों पर पुलिया और रिटेनिंग वॉल बनाई जाएगी। अतरहट–खप्टिहा–साड़ी मार्ग की विशेष मरम्मत के साथ रिटेनिंग वॉल का निर्माण कराया जाएगा। दोहतरा–बेंदाघाट जलालपुर मार्ग की भी मरम्मत होगी। नांदादेव–पड़ोहरा संपर्क मार्ग पर चंद्रावल नदी के पहले से बने रपटे की विशेष मरम्मत कराई जाएगी। इससे नदी पार करने वाले ग्रामीणों को सहूलियत मिलेगी। पैलानी–गलौली मार्ग पर विशेष मरम्मत के साथ सुरक्षा संबंधी कार्य होंगे। वहीं, तिंदवारी–गोधनी मार्ग पर अरसौड़ा और आबादी संपर्क मार्ग की मरम्मत कराई जाएगी। एक्सईएन लोक निर्माण विभाग मनोज कुमार पांडेय ने बताया कि कार्यों के लिए टेंडर जारी किए जा रहे हैं। प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य शुरू करा दिए जाएंगे।

पीड़ित पति ने अपनी पत्नी व सास द्वारा झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देने का लगाया आरोप

न्याय नहीं मिला तो एसएसपी,डीआईजी व अदालत की शरण मे जाएगा पीडित पति

अयोध्या। कोतवाली नगर क्षेत्र के कंधारी बाजार रिकाबगंज निवासी पीड़ित पति अब्दुल रहमान ने अपनी पत्नी और सास द्वारा झूठे मुकदमों में फंसाने तथा दहेज समेत अन्य मामलों में कार्रवाई कराने की धमकी देने का आरोप लगाया है।पीड़ित ने अपनी पत्नी मिस्बा खातून निवासी तोरोमाफी दराबगंज कोतवाली बीकापुर और सास समीरा बानों पर आरोप लगाया कि उसकी पत्नी व सास की ओर से उसे लगातार विभिन्न मुकदमों में फंसाने की धमकी दी जा रही है।बताया



कि दहेज सहित अन्य मामलों में झूठे आरोप लगाकर कानूनी कार्रवाई कराने की बात कहकर उसे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है।पीड़ित पति का कहना है कि इस तरह की धमकियों के चलते वह खुद को असहज और भयभीत महसूस कर रहा है।पीड़ित ने अपनी पत्नी,साली तथा सास के खिलाफ बीकापुर कोतवाली में कई गंभीर धाराओं में मामले भी दर्ज है।पीडित पति अब्दुल रहमान ने बताया कि अगर उसे अनावश्यक रूप से मुकदमों में फंसाने और धमकाया जाता है तो वह न्याय की उम्मीद लेकर एसएसपी, डीआईजी के कार्यालय पहुंचकर न्याय के लिए दरवाजे खटखटाएगा।वहां भी न्याय नहीं मिलने पर मजबूरी मे अदालत का सहारा लेगा।

आरटीओ कार्यालय अयोध्या में परिवहन मेले का भव्य आयोजन 28.72 लाख रुपये का बकाया राजस्व जमा



अयोध्या।परिवहन विभाग द्वारा संभागीय परिवहन कार्यालय,अयोध्या में परिवहन मेले का आयोजन किया गया।इस अवसर पर एआरटीओ (प्रशासन) डॉ आर.पी. सिंह तथा मोटर वाहन निरीक्षक राजीव गुप्ता उपस्थित रहे।परिवहन मेले में ट्रक यूनियन, बस यूनियन एवं टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों के साथ–साथ 75 से अधिक ट्रांसपोर्टरों एवं वाहन स्वामियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।इस मौके पर एआरटीओ प्रशासन डॉक्टर आरती सिंह ने बताया कि मेले का मुख्य उद्देश्य वाहन स्वामियों एवं ट्रांसपोर्टरों को परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना तथा उनके वाहनों पर लंबित कर एवं अन्य बकाया देयताओं के निस्तारण में सहायता प्रदान करना था।मेले के दौरान शासन के प्रावधानों के अंतर्गत वाहन स्वामियों को बकाया टैक्स पर देय पेनल्टी में छूट का लाभ प्रदान करते हुए उनके बकाया कर का भुगतान कराया गया। इसके परिणामस्वरूप कुल 28 वाहनों से 28.72 लाख रुपये का बकाया राजस्व सायं 5:00 बजे तक जमा कराया गया।मेले में विभिन्न परिवहन सेवाओं एवं बकाया कर निस्तारण की सुविधा से 85 वाहन स्वामी लाभान्वित हुए।अधिकारियों द्वारा वाहन स्वामियों को वाहन पंजीकरण,परमिट,फिटनेस प्रमाण–पत्र, कर भुगतान, पेनल्टी में छूट तथा अन्य परिवहन संबंधी सेवाओं एवं प्रक्रियाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि परिवहन मेले के माध्यम से विभाग और वाहन स्वामियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, परिवहन सेवाओं को सरल एवं सुलभ बनाने तथा बकाया राजस्व की वसूली में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार के आयोजनों से वाहन स्वामियों को एक ही स्थान पर विभिन्न समस्याओं के समाधान की सुविधा प्राप्त होती है।परिवहन विभाग द्वारा 25 दिसंबर 2026 को भी जनहित एवं वाहन स्वामियों की सुविधा के दृष्टिगत इस प्रकार का परिवहन मेला आयोजित किया जाएगा।

नीलकंठ धाम में तीसरे दिन भी भक्तों की भीड़ ने स्नान के बाद किया जलाभिषेक

बांदा, संवाददाता। ऐतिहासिक कालिंजर दुर्ग में आयोजित कार्तिक पूर्णिमा मेले के तीसरे दिन भी आस्था का सैलाब उमड़ा। सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। भक्तों ने दुर्ग स्थित प्राचीन तालाबों में स्नान किया। इसके बाद भगवान नीलकंठ महादेव के दरबार में पहुंचकर जलाभिषेक व पूजन किया। तीन दिनों से चल रहे मेले में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है।

सतपाल अंतिल बने अयोध्या के नए एसएसपी,एसएसपी,डाक्टर गौरव ग्रोवर बने एसएसपी मुरादाबाद

अयोध्या।वर्ष 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी सतपाल अंतिल अब अयोध्या जिले के नये एसएसपी बनाये गये है।जबकि अयोध्या मे एसएसपी रहे डॉ. गौरव ग्रोवर को मुरादाबाद एसएसपी के रुप मे जिम्मेदारी दी गई है।बताते चले कि नवागत एसएसपी सतपाल अंतिल जून 2024 से मुरादाबाद के एसएसपी के पद पर तैनात थे। इससे पहले वे प्रतापगढ़ और फतेहपुर समेत अन्य जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं।वह उत्तर प्रदेश कैडर के 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।वहीं,अयोध्या में एसएसपी के पद पर तैनात डॉ. गौरव ग्रोवर को मुरादाबाद का एसएसपी बनाया गया है।दोनों



अधिकारियों के स्थानांतरण से अयोध्या और मुरादाबाद में पुलिस नेतृत्व में बदलाव होगा।धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण अयोध्या में नए एसएसपी सतपाल अंतिल के सामने कानून–व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने, राम मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं की भीड़ के प्रबंधन तथा आगामी धार्मिक आयोजनों के साथ साथ आगामी चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

जिला अस्पताल परिसर से एक माह में चार बाइक चोरी

अयोध्या। जिला चिकित्सालय परिसर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं।जिसके चलते यहाँ इलाज कराने आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के वाहन लगातार चोरों के निशाने पर हैं।बीते एक माह के भीतर अस्पताल परिसर से चार मोटरसाइकिल चोरी होने की घटनाएं सामने आई हैं।लगातार हो रही वारदातों से अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मालूम हो कि कोतवाली नगर क्षेत्र के राठ हवेली निवासी मोहम्मद काशिफ पुत्र शहजादे अपने भाई साकिब को लेकर करीब ढाई बजे जिला चिकित्सालय पहुंचे थे। उन्होंने अस्पताल के पुराने साइकिल स्टैंड के पास अपनी बाइक खड़ी कर इमरजेंसी वार्ड में चले गए।कुछ देर बाद वापस लौटे तो बाइक गायब मिली। काफी खोजबीन के बाद भी मोटरसाइकिल का पता नहीं चला।पीड़ित ने डायल 112 पर फोन कर घटना की सूचना दी।इसके बाद रकाबगंज चौकी पहुंचकर पुलिस को भी मामले से अवगत कराया।मिली जानकारी के मुताबिक जिला अस्पताल परिसर में इससे पहले भी अलग–अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं।मगलसी, सोहावल और गौरा पट्टी क्षेत्र के लोगों की मोटरसाइकिल चोरी होने की घटनाएं भी सामने आई हैं।इसके अलावा एक साइकिल भी चोरी हो चुकी है।फिलहाल लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के बीच अस्पताल परिसर में वाहनों की सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था की मांग उठने लगी है। मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि अस्पताल में इलाज कराने के दौरान वाहन चोरी होने से उन्हें आर्थिक नुकसान और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।ऐसे में जिला अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने और चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की जरूरत है।

जलवायु सम्मेलन में भारत की आवाज बने बांदा के डा. चंद्रशेखर द्विवेदी



बांदा, संवाददाता। तुर्किये के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी–31) में जिले के शिक्षाविद् डॉ. चंद्रशेखर द्विवेदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उन्हें भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया था। सम्मेलन के दौरान उन्होंने जलवायु न्याय, पर्यावरण संरक्षण और विकासशील देशों के अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। वर्तमान में झारखंड केंद्रीय विवि रांची में प्रोफेसर डॉ. द्विवेदी ने कोट डी आइवर के पवेलियन में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सत्र में पैनलिस्ट के रूप में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि जलवायु संकट के समाधान में औद्योगिक देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वैश्विक कार्बन बजट का न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करने के साथ विकासशील देशों के विकास के अधिकारों की रक्षा जरूरी है। उन्होंने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के अनुरूप विकसित देशों से विकासशील देशों को पर्याप्त और सुलभ जलवायु वित्त उपलब्ध कराने तथा जलवायु अनुकूलन के लिए आर्थिक सहयोग बढ़ाने की पैरवी की।

डॉ. द्विवेदी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सदस्य (आरईसी) के रूप में भी संबद्ध हैं। उनका शोध कार्य जियोइन्फॉर्मेटिक्स, पर्यावरण प्रबंधन, भूमि पुनर्वास, जैव उपचार और पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है। उनकी इस उपलब्धि पर बांदा के बंगालीपुरा निवासी बड़े भाई अधिवक्ता अरविंद द्विवेदी, भतीजे शेखर शरण द्विवेदी, प्रवक्ता दिशा द्विवेदी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमित सेठ भोलू और पद्मश्री उमाशंकर पांडेय ने खुशी जताई। उन्होंने इसे बुंदेलखंड के युवाओं और शोधार्थियों के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि बताया।

करंट से शिक्षक की पत्नी और युवक की मौत

सुल्तानपुर, संवाददाता। जिले के अलग–अलग स्थानों पर बुधवार को करंट की चपेट में आने से शिक्षक की पत्नी और एक युवक की मौत हो गई। अखंडनगर के टिकरी गांव में डीजे की मरम्मत करते समय आजमगढ़ जिले के पवई क्षेत्र के हेवती निवासी राम कुमार (38) करंट की चपेट में आ गए। वहीं, जयसिंहपुर के खमपुर गांव में बाथरूम में लगे हैंडपंप में उतरे करंट की चपेट में आने से शिक्षक रामतीर्थ कनौजिया की पत्नी बसंती देवी (48) की मौत हो गई। आजमगढ़ जिले के पवई क्षेत्र के हेवती निवासी राम कुमार की ससुराल अखंडनगर के टिकरी गांव में है। परिजनों के मुताबिक, बुधवार भोर करीब चार बजे टिकरी गांव में डीजे की मरम्मत करते समय राम कुमार करंट की चपेट में आकर झुलस गए। परिजन उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अखंडनगर ले गए, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अखंडनगर थाने के प्रभारी निरीक्षक धीरेंद्र वर्मा ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उधर, जयसिंहपुर के खमपुर निवासी रामतीर्थ कनौजिया की पत्नी बसंती देवी बुधवार सुबह करीब आठ बजे पुराने मकान में बने बाथरूम में स्नान करने गई थीं। बाथरूम में लगे हैंडपंप में टुल्लू पंप भी लगा है। परिजनों के मुताबिक, हैंडपंप छूते ही बसंती देवी करंट की चपेट में आकर गिर पड़ीं। कुछ देर बाद परिजन बाथरूम के पास पहुंचे तो उन्हें जमीन पर बेहोश पड़ा देखा। परिजन मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने गांव के बाहर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जयसिंहपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विवेक राय ने बताया कि तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के पवई क्षेत्र के हेवती निवासी राम कुमार करीब 10 साल से अपनी ससुराल अखंडनगर के टिकरी गांव में रह रहे थे। उन्होंने यहां जमीन खरीदी थी, लेकिन मकान नहीं बनवाया था। वह डीजे संचालन, बिजली उपकरणों की दुकान चलाने, उनकी मरम्मत करने और पिकअप चलाने का काम करते थे। उनकी मौत से पत्नी सीमा और दो पुत्र प्रिंस (15) व रतन (12) सदमे में हैं। वहीं, जयसिंहपुर के खमपुर निवासी शिक्षक रामतीर्थ की पत्नी बसंती देवी की मौत से बेटी अंजली (25) और बेटे मनीष (20) व नैतिक (16) भी सदमे में हैं। रामतीर्थ धनपतगंज ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय कनकपुर शिकवा में शिक्षक हैं।

रबी सीजन के लिए 21 हजार मीट्रिक टन से अधिक खाद उपलब्ध

बांदा, संवाददाता। रबी फसलों की बोआई का समय और डीएपी के लिए मची हाय–तौबा के बीच विभाग ने जिले में उर्वरकों की उपलब्धता पर्याप्त बताई है। कृषि विभाग के अनुसार किसानों की मांग के अनुरूप सहकारी समितियों और निजी विक्रेताओं के माध्यम से खाद की आपूर्ति लगातार की जा रही है। किसी भी क्षेत्र में उर्वरक की कमी नहीं होने देने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कृषि अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि जिले में वर्तमान में 15,493 मीट्रिक टन यूरिया, 2157 मीट्रिक टन डीएपी, 2528 मीट्रिक टन एनपीके और 882 मीट्रिक टन एसएसपी उपलब्ध है। विक्रेताओं को स्टॉक बनाए रखने, निर्धारित दरों पर बिक्री करने और दुकानें बिना सूचना बंद न रखने के निर्देश दिए गए हैं। रात आठ बजे के बाद बिक्री करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। उर्वरक वितरण में पारदर्शिता के लिए किसानों को फार्मर रजिस्ट्री या खतौनी के आधार पर पॉश मशीन से खाद लेने के लिए कहा गया है। मशीन पर किसान के अंगूठा लगाने पर चालू माह और सीजन में पहले खरीदे गए उर्वरक का विवरण भी दिखाई देगा। उपलब्ध क्षेत्रफल के अनुसार खाद दी जाएगी। विक्रेताओं को स्टॉक और रेट बोर्ड प्रदर्शित करने, डीएपी उपलब्ध होने पर बोरियां सामने रखने, बिक्री की रसीद देने और पॉश मशीन में पेपर रोल रखने के निर्देश हैं। जिला कृषि अधिकारी ने चेताया कि स्टॉक होने के बावजूद बिक्री न करना कालाबाजारी की मंशा माना जाएगा। अधिक मूल्य वसूली, नकली खाद बेचने या जबरन अन्य उत्पाद देने की शिकायत सही मिलने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी।

24 हजार परिवारों को गैस कनेक्शन का इंतजार

सुल्तानपुर, संवाददाता। जिले में आठ माह से नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी नहीं हो रहे हैं। पेट्रोलियम कंपनी की ओर से मार्च 2026 से 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू कनेक्शन जारी करने पर रोक लगाए जाने से 24 हजार से अधिक परिवारों के आवेदन लंबित हैं। नए कनेक्शन की आस में लोग लगातार गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं। विकल्प के तौर पर छोटे सिलिंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन इनकी कीमत अधिक होने से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। कई परिवार अब व्यावसायिक सिलिंडर खरीदने को मजबूर हैं। जिले में 48 गैस एजेंसियों के माध्यम से करीब 5.59 लाख उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति की जा रही है। शहर के नए विकसित इलाकों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नए कनेक्शन की मांग कर रहे हैं। एजेंसी संचालकों के मुताबिक, पीएनजी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मार्च 2026 से घरेलू गैस कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया बंद है। जिले में भी पीएनजी की शुरुआत नहीं हुई है। कनेक्शन के लिए एजेंसियों पर पहुंचने वाले लोगों को पोर्टल बंद होने या उच्च स्तर से रोक होने की बात कहकर लौटा दिया जाता है।

छोटे सिलिंडर की कीमत भी अधिक

नया घरेलू कनेक्शन नहीं मिलने से जरूरतमंद परिवारों को खाना पकाने के लिए छोटे या व्यावसायिक सिलिंडर का सहारा लेना पड़ रहा है। घरेलू सिलिंडर की कीमत 996.50 रुपये है, जबकि पांच किलो का सिलिंडर 823 रुपये और 10 किलो का सिलिंडर 1,650 रुपये में मिल रहा है। वहीं, 19 किलो का व्यावसायिक सिलिंडर 2,988 रुपये में मिल रहा है। ऐसे में परिवारों का रसोई बजट प्रभावित हो रहा है।

कई महीनों से लगा रहे एजेंसियों के चक्कर

शहर के विवेक नगर निवासी राजेंद्र कुमार ने बताया कि नए कनेक्शन के लिए कई महीनों से एजेंसी और पूर्ति विभाग के चक्कर लगा रहे हैं।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।